>

Title: Need to enhance the budgetary allocation to Uttar Pradesh.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और तमाम दलों के सम्मानित सदस्यों ने अपने राज्यों की बात उठाई। रघुराम राजन समिति की रिपोर्ट के बारे में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि उस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जो देश के पिछड़े राज्य हैं, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश हैं, इनको विशेष राज्य का दर्जा देकर पैकेज दिया जाए। ऐसे राज्यों को आप विशेष राज्य का दर्जा देकर आर्थिक तौर पर मज़बूत करें और वहाँ का विकास करें। लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट में पूर्वांचल, बुंदेलखंड तथा जो पिछड़े इलाके हैं, उनका ज़िक्र भी हुआ है कि वहाँ जीडीपी का क्या रेट है। इस प्रकार से वहाँ के लोगों का क्या जीवन स्तर है, इसका बड़े विस्तार से मूल्यांकन किया है। उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किया गया। पिछला जो वार्षिक योजना का बजट था, केवल तीस फीसदी दिया गया, 70 फीसदी रोक दिया गया। मैं चाहूँगा कि केन्द्र सरकार जो पक्षपात कर रही है, गैर-भाजपा शासित जो राज्य हैं, वहाँ सौ प्रतिशत जाता है, वहाँ विशेष पैकेज देते हैं, लेकिन जहाँ पर तमाम ऐसी सरकारें हैं जो इनकी पार्टी की नहीं हैं, वहाँ पर वार्षिक बजट में कटौती की जा रही है। मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश को100 परसेंट बजट के साथ-साथ 80 हज़ार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया जाए, तभी देश का विकास हो सकता है। यह इसलिए कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। वहाँ पर लोक सभा की 80 सीट हैं। देश का हृदय प्रदेश उत्तर प्रदेश है। इसलिए हम चाहेंगे कि वित्त मंत्री जी का जो बयान कल आया है, रघुराम राजन रिपोर्ट के बारे में, वह भ्रमित करने वाला है। एक तरीके से पूरे सदन को उन्होंने मिसगाइड किया है। यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री पबन सिंह घाटोवार जी बैठे हैं। हम चाहेंगे कि वे खड़े होकर जवाब दें ताकि चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, जेडीयू के लोग हों, तमाम राज्यों के लोग हों, वे संतुष्ट हो पाएँ। आप यहाँ खड़े होकर कहिए कि इस बात को हम सरकार को इंगित करेंगे, सरकार को ध्यान दिलाएँगे, तभी हम संतुष्ट हो पाएँगे। आप इस पर खड़े होकर जवाब दीजिए। ...(व्यवधान) मंत्री जी, आप कुछ तो बोलिये। ...(व्यवधान)